

हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर रपिर्ट

चर्चा में क्यों?

एक हालिया सरकारी रपिर्ट से पता चला है कि राज्य में 19 स्कूल बना किसी छात्र के हैं, 811 स्कूलों में सरिफ एक शकिषक है और कुल 3,148 स्कूलों में उनकी कषमता के आधे से भी कम छात्र हैं।

मुख्य बदि:

- रपिर्ट, जसिमें फरवरी 2024 में केंद्रीय शकिषा मंत्रालय के परयोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा आयोजति एक बैठक के मुख्य बदिओं को रेखांकति कथिा गया, जसिमें राज्य के 14,562 सरकारी स्कूलों को चहिनति कथिा गया।
- रपिर्ट ने वशिषकर प्राथमकि वदियालयों में शकिषकों की अपर्याप्त संख्या पर प्रकाश डाला और सरकार को इन रकिर्तियों को तुरंत भरने की सलाह दी।
- शकिषकों की कमी का असर वेतन भुगतान के लयि आवंटति केंद्रीय धनराशिपर पड़ा है।
- प्राथमकि कषेत्र में, वत्तीय सहायता वर्ष 2021-22 की अवधिमें 19 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गई है।
- इसी तरह, उच्च शकिषा में कई रकिर्त पदों के कारण अनुदान 20 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गया है।
- रपिर्ट में शकिषकों की कमी के अलावा इन स्कूलों में छात्रों के लयि बुनयादी ढाँचे की कमी की भी बात कही गई है।
- जबकि स्कूल अतरिकित कक्षाओं के अपने लक्ष्य से 18% कम हैं, लड़कों और लड़कियों के लयि शौचालय 1% व 1.8% कम हैं। स्मार्ट क्लासरूम भी आवश्यक संख्या से 1.4% कम हैं।
- रपिर्ट में इस बात पर ज़ोर दथिा गया है कि अतीत की गैर-आवर्ती स्वीकृतियों, जनि पर वर्षों से राज्य द्वारा ध्यान नहीं दथिा गया है, अंततः **समग्र शकिषा फरेमवरक** के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के बाद राज्य की एकमात्र ज़मिमेदारी बन जाएंगी।
- जनि स्कूलों ने सुवधिएँ स्थापति नहीं की हैं, उन्हें अपने प्रारंभकि प्रस्ताव वापस लेने चाहयि और नए प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहयि।
- प्रस्तुत आँकड़ों में कसिी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लयि राज्य सरकार को लंबति कार्यों की प्रगतिको नथिमति रूप से **प्रबंध पोर्टल** पर अपडेट करने का नरिदेश दथिा गया है।

समग्र शकिषा योजना

- यह स्कूली शकिषा के लयि एक एकीकृत योजना है, जसिमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शकिषा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल कथिा गया है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शकिषा प्रदान करना है।
- यह 'सर्व शकिषा अभयान' (SSA), 'राष्ट्रीय माध्यमकि शकिषा अभयान' (RMSA) और 'शकिषक शकिषा' (TE) की तीन योजनाओं को समाहति करती है।
- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शकिषक (पूर्व-प्राथमकि से वरषिठ माध्यमकि स्तर तक) शामिल हैं।
- इसे केंद्र परायोजति योजना के रूप में लागू कथिा जा रहा है। इसमें केंद्र और अधकिंश राज्यों के बीच वत्तिपोषण में 60:40 का वभिजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शकिषा मंत्रालय द्वारा लॉन्च कथिा गया था।

समग्र शकिषा योजना 2.0

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT):**
 - योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लयि सभी बाल-केंद्रति हस्तकषेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारति प्लेटफॉर्म पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर शकिषा का अधकिार पात्रता के तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस और परविहन भत्ते प्रदान कथिे जाएंगे।
- NEP की सफिरशें:**
 - भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:
 - इसमें भाषा शकिषकों की नयिकृति के लयि एक नया घटक है, जसिमें वेतन और प्रशकिषण लागत के साथ-साथ द्वभिषी कतिाबें तथा शकिषण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP में अनुशंसति कथिा गया है।

- **पूरव पूरथमकि शकिषा:**
 - इसमें अब शकिषण एवं अधगिम सामगरी, स्वदेशी खलौने और खेल तथा खेल-आधारति गतविधियों के लयि सरकारी स्कूलों में पूरव-पूरथमकि वर्गों को समर्थन देने के लयि वतित प्रदान करना शामिल होगा ।
 - योजना के तहत पूरव-पूरथमकि शकिषकों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लयि कुशल प्रशकिषकों का समर्थन कयिा जाएगा ।
- **नपुिण भारत पहल:**
 - इस पहल के तहत शकिषण सामगरी के लयि प्रतति छात्र 500 रुपए, मैनुअल और संसाधनों के लयि प्रतति शकिषक 150 रुपए तथा आधारभूत साक्षरता एवं अंकगणति के आकलन के लयि प्रतति जिले 10-20 लाख रुपए का वार्षकि प्रारवधान है ।
- **डजिटिल पहल:**
 - डजिटिल बोरड, वर्चुअल क्लासरूम और DTH चैनलों के लयि समर्थन सहति ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का प्रारवधान है, जो कोवडि-19 महामारी के मद्देनजर अधकि महत्त्वपूरण हो गए हैं ।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:**
 - इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलगि के माध्यम से अपनी शकिषा पूरी करने के लयि 2000 प्रतति ग्रेड के वतितपोषण का समर्थन देने का प्रारवधान शामिल है ।
 - स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों दोनों के लयि कौशल तथा व्यावसायकि शकिषा पर भी अधकि ध्यान दयिा जाएगा ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/report-on-haryana-government-schools>

